बी. रामाकिचेनिन बालगांधी

बनाम

भारत संघ व अन्य

16 नवंबर, 2007

[ए.के. माथुर और मार्कंडेय कातजू, जेजे.]

सेवा कानूनः

साक्षात्कार के माध्यम से चयन- उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूचीः- चयन निकाय द्वारा संक्षिप्त सूचीकरण की विधि को वैध रूप से अपनाया जा सकता है। बशर्ते कि इसका कुछ तर्कसंगत या वस्तुनिष्ठ आधार हो-यदि एक संक्षिप्त विधि नियम या विज्ञापन में सूची निर्धारित की गई है तो केवल विधि का पालन करना होगा-तथ्यों पर, जमीनी स्तर पर संक्षिप्त सूचीकरण। एम. एससी. डिग्री के बाद दो साल के अनुभव को बनाए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि लघु-सूचीकरण की विधि प्रदान करने वाला विज्ञापन उल्लेख नहीं करता है कि अनुभव एम. एससी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद होना चाहिए। दो साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति एम. एससी. की डिग्री प्राप्त करने से पूव बरकरार रखा गया।

उप निदेशक (कृषि) के पद के लिए विज्ञापन एम. एससी. की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कृषि में और विस्तार कार्य/मिट्टी/निवेश में दो साल का अनुभव विश्लेषण करें। अपीलार्थी ने पद के लिए आवेदन किया। यूपीएससी इस आधार पर संक्षिप्त सूचीकरण किया कि उन्हें प्राप्त करने के बाद दो साल का अनुभव नहीं था एम.एससी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क देते हुए एक ओ.ए. दायर किया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि दो साल का अनुभव एम.एससी प्राप्त करने के

बाद होना चाहिए। डिग्री और जैसा कि उन्हें प्राप्त करने से पहले आवश्यक अनुभव था एम.एससी की डिग्री लेने के बाद उन्होंने आवश्यक शर्तों को पूरा किया। न्यायाधिकरण के दिशा निर्देश पर अपीलार्थी का साक्षात्कार लिया गया था; और जब से वह खड़ा था योग्यता सूची में सबसे पहले उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसने अपीलाथी के आवेदन यह प्रतिपादित करते हुए खारिज कर दिया कि यूपीएससी द्वारा अपनाई गई सूचीकरण की विधि में कोई अवैधता नहीं थी। पिडित उम्मीदवार ने अपील दायर की।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. यह अच्छी तरह से तय है कि लघु-सूचीकरण की विधि कर सकती है चयन निकाय द्वारा वैध रूप से अपनाई जा सकती है। भले ही कोई नियम न हो संक्षिप्त सूची का प्रावधान करना और न ही विज्ञापन में इसका कोई उल्लेख करन पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने पर चयन निकाय सहारा ले सकता है एक छोटी सूची प्रक्रिया के लिए यदि बड़ी संख्या में पात्र हैं उम्मीदवारों और प्राधिकरण के लिए सभी का साक्षात्कार करना संभव नहीं है उन्हें संक्षिप्त सूचीकरण की प्रक्रिया केवल मीडिया के माध्यम से एक व्यावहारिक प्रक्रिया है। जिसके बाद से अदालतों द्वारा विभिन्न निर्णयों में इसका पालन किया गया है अन्यथा चयन के लिए बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं औरअधिकारियों की नियुक्ति क्योंकि वे सैकड़ों लोगों का साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं दो आवश्यकताएँ होनी चाहिए-(i) यह कुछ तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ आधार पर होनी चाहिए और (ii) यदि संक्षिप्त सूचीकरण की एक निर्धारित विधि है। नियम या विज्ञापन में उल्लेख किया गया है तो उस विधि का केवल पालन करना पड़ता है। [पैरा 15, 16 और 17] [125-सी, डी, ई, एफ; 126-ए]

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम नवनीत कुमार; पोटदार और अन्य, [1994] 6 एससीसी 293; और आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. दिलीप कुमार और अन्य, [1993] 2 एससीसी 310, आदि, पर निर्भर थे।

1.2. आम तौर पर, न्यायालय प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। निर्णय लेते हैं। हालांकि, हस्तगत मामले 'के अनुच्छेद 3.1 में यूपीएससी के विज्ञापन दिनांक 23.5.1998, में शॉर्टलिस्टिंग की विधि दी गई है। इसलिए यूपीएससी किसी अन्य विधि का सहारा नहीं ले सकता है, पैराग्राफ 3.1 में निर्धारित की गई छोटी सूची के अलावा। उक्त अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि आयोग न्यूनतम से अधिक योग्यता और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या को सीमित कर सकता है। विज्ञापन में अनुभव के आधार पर या उस पर निर्धारित न्यूनतम से अधिक संबंधित क्षेत्र में अनुभव का आधार। प्राप्त करने के बाद अनुभव एमएससी डिग्री प्राप्त करने से पहले या इसके अलावा, विज्ञापन दिनांकित था 23.5.1998 यह उल्लेख नहीं है कि दो साल का अनुभव एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद होना चाहिए। अतः न्यायालय इसमें शब्द नहीं जोड़ सकता। विज्ञापन और इसे वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे वह है। [पैरा 18, 20 और 21] [126-बी, डी, ई, एफ, जी; 127-ए-बी]

रमण दयाराम शेट्टी बनाम। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य एआईआर (1979) एससी 1628 पर भरोसा किया।

टाटा सेल्युलर वी. भारत संघ, एआईआर (1996) एससी 11 का उल्लेख किया गया है।

1.3. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी तब से उप निदेशक (कृषि) के रूप में कार्य कर रहा है। 2001 न्यायाधिकरण के निर्णय

और अंतरिम आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय के उनकी नियुक्ति की पुष्टी की जाती है। [पैरा 24] [128-ई, एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5274/2007।

मद्रास उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं. 9521, 18563/2000 और 21870/2001 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.9.2006 से।

अपीलार्थी के लिए आर. वेंकटरमानी, जी. उमापति और राकेश के. शर्मा,

उत्तरदाताओं के लिए बीनू टम्टा, एस. अरविंद, सुजीत कुमार, वी. रामसुब्रमण्यन, पी.वी. योगेश्वरन, वी.जी. प्रगसम, एस. जोसेफ अरस्तू और एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन।

न्यायालय का निर्णय मार्कंडेय काटजू, जे. द्वारा सुनाया गया था।

1. अनुमति दी गई

2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं. 9521, 18563/2000 और 21870/2001 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.9.2006 के विरुद्ध दायर की गई है।

3. पक्षों की ओर से विद्वानों की सलाह सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

4. अपीलार्थी (रिट याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 3) ने इसके लिए आवेदन कृषि विभाग पांडीचेरी सरकार में उप निदेशक (कृषि) का पद, के लिए किया। उस पद को सीधे भरा जाना था संघ लोक द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में भर्ती सेवा आयोग (इसके बाद संक्षेप में 'यूपीएससी') दिनांक 23.5.1998 योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

5. अपीलार्थी का कहना है कि वह इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य था, लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, हालांकि समान रूप से रखे गए उम्मीदवारो को बनाया गया था।

6. इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि विज्ञापन में यूपीएससी द्वारा जारी पद के लिए, उसमें उल्लिखित आवश्यक योग्यताएँ वे इस प्रकार थेः

"आवश्यकः

एः शैक्षिकः एमएससी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि में डिग्री विश्वविद्यालय या संस्थान।

बीः अनुभवः विस्तार कार्य/मिट्टी/निवेश में दो साल का अनुभव

विश्लेषण।"

विज्ञापन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि दो का अनुभव एम. एससी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद के साल होने चाहिए।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि यूपीएससी ने शॉर्टलिस्टिंग का सहारा लिया और ऐसा नहीं किया एम. एससी. प्राप्त करने के बाद विस्तार कार्य/मिट्टी/निवेश विश्लेषण में अनुभव। कृषि में डिग्री। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके पास अपेक्षित अनुभव था, लेकिन एम. एससी. की डिग्री प्राप्त करने से पहले प्राप्त किया गया था। यूपीएससी ने केवल उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था जिन्हे डिग्री प्राप्त करने के बाद अनुभव प्राप्त हुआ था।

8. अपीलार्थी का मत था कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि दो साल का अनुभव परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद होना चाहिए कृषि में। अपीलार्थी को निस्संदेह पहले भी ऐसा अनुभव कृषि में एम. एससी. की डिग्री प्राप्त करने से पूर्व का था।

9. चूंकि अपीलार्थी को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था, इसलिए उन्होंने ओ.ए. दायर किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चेन्नई के समक्ष 1045/97। एक अंतरिम आदेश में न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी। तत्पश्चात न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 23.6.2000 में कहा कि चूंकि अपीलार्थी का साक्षात्कार अंतरिम आदेश के अनुसरण में किया गया था परिणाम प्रकाशित किया गया था और चूंकि अपीलार्थी योग्यता में पहले पाया गया था सूची में, उन्हें 23.3.2001 पर उप निदेशक (कृषि) के रूप में नियुक्त किया गया था, और तब से इस तरह काम कर रहा है।

10. पीड़ित, रिट याचिका उत्तरदाताओं द्वारा यहाँ दायर की गई थी अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द कर दिया। अतः इस तरह की अपील विशेष अनुमति याचिका के जरिए।

11. उच्च न्यायालय द्वारा अलग रखने के लिए दिए गए कारणों में से एक अपीलार्थी की नियुक्ति यह थी कि न्यायाधिकरण को इस मामले में जाना चाहिए था यूपीएससी को परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश देकर उसके समक्ष दायर ओ.ए को हटा दें। तदनुसार, इसमें अपीलार्थी की नियुक्ति पांडिचेरी सरकार द्वारा कृषि उप निदेशक के पद पर 23.3.2001 दिनांकित आदेश के माध्यम से की थी।

12. हमें इस सवाल में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या न्यायाधिकरण को जाना चाहिए। हमने मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि हम इसे गुण-दोष के आधार पर तय कर रहे हैं।

13. उच्च न्यायालय ने भी विवादित फैसले में कहा है कि कि यह यूपीएससी के लिए उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए खुला था संक्षिप्त सूचीकरण विधि अपनाकर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। उच्च न्यायालय का यह मत था कि विधि

में कोई तर्कहीनता या अवैधता नहीं थी (यूपीएससी द्वारा अपनाई गई संक्षिप्त सूची) सम्मान के साथ, हम सहमत नहीं हो सकते।

14. यूपीएससी के विज्ञापन दिनांकित 23.5.1998, के अनुच्छेद 3.1 में यह कहा गया हैः-

> "जहाँ एक के जवाब में प्राप्त आवेदनों की संख्या विज्ञापन बड़ा है और यह सुविधाजनक या संभव नहीं होगा आयोग सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेगा, पर उम्मीदवारों की संख्या को एक उचित सीमा तक सीमित कर सकते हैं। न्यूनतम से अधिक योग्यता और अनुभव के आधार पर विज्ञापन में या अनुभव के आधार पर निर्धारित विज्ञापन में या उस निर्धारित न्यूनतम से अधिक संबंधित क्षेत्र में अनुभव के आधार पर, या एक जांच आयोजित करके परीक्षण इसलिए उम्मीदवार को सभी योग्यताओं का उल्लेख करना चाहिए और न्यूनतम से अधिक प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव योग्यताएँ और इसकी सत्यापित/स्व-प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी चाहिए उनके समर्थन में प्रमाण पत्र।"

15. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संक्षिप्त सूचीकरण की विधि वैध हो सकती है। (पैरा 6, 8, 9 और 13) और आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. दिलीप कुमार और अन्य, [1993] 2 एससीसी 310, आदि।

16. भले ही लघु-सूचीकरण के लिए कोई नियम न हो और न ही कोई उल्लेख हो। पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में, चयन यदि बड़ी संख्या है तो निकाय एक छोटी सूची प्रक्रिया का सहारा ले सकता है। योग्य उम्मीदवार जो आवेदन करते हैं और प्राधिकरण के लिए उन सभी का साक्षात्कार करना संभव नहीं है। उदाहरण

के लिए, यदि एक या दो पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से प्राप्त 1000 से अधिक आवेदन, यह नहीं हो सकता है चयन निकाय द्वारा सूचीकरण का सहारा लिया जा सकता है, भले ही कोई नहीं है नियमों में या विज्ञापन में संक्षिप्त सूची का उल्लेख करें।

17. हालांकि, वैध लघु-सूचीकरण के लिए दो होने चाहिए आवश्यकताएँ-(i) यह कुछ तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए उदाहरण के लिए, यदि चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना है जिसके लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता एक बीएससी डिग्री है, और यदि बड़ी संख्या में हैं योग्य आवेदकों में से, चयन निकाय द्वारा संक्षिप्त सूची का सहारा लिया जा सकता है बी.एससी में कुछ न्यूनतम अंक निर्धारित करना और केवल वे जिन्होंने प्राप्त किए हैं ऐसे अंकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। यह किया जा सकता है, भले ही नियम या विज्ञापन में केवल उन लोगों का उल्लेख नहीं है जिनके पास उपरोक्त न्यूनतम अंकों पर विचार किया जाएगा या नियुक्त किया जाएगा पोस्ट करें। इस प्रकार लघु-सूचीकरण की प्रक्रिया केवल एक व्यावहारिक माध्यम है जो विभिन्न निर्णयों में अदालतों द्वारा अनुसरण किया गया है क्योंकि अन्यथा वहाँ अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के लिए बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं क्योंकि वे सैकड़ों और हजारों योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं हो सकता है;

(ii) यदि संक्षिप्त सूचीकरण की एक निर्धारित विधि का उल्लेख नियम या विज्ञापन में किया गया है तो केवल उसी विधि का पालन करना पड़ता है।

18. वर्तमान मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपीएससी ने एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदंड कि केवल वे जिनके पास दो साल एम. एससी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद के अनुभव है पर विचार किया जाएगा, जबकि टाटा सेल्युलर वी. भारत

संघ, आकाशवाणी (1996) एससी 11. जैसा कि देखा गया है उक्त निर्णय, प्रशासनिक मामलों में आधुनिक दृष्टिकोण अदालतों के लिए संयम का पालन करना है।

19. इसलिए, यदि संक्षिप्त सूचीकरण की विधि निर्धारित नहीं की गई थी यू. पी. एस. सी. द्वारा या किसी वैधानिक नियम में, यह संभव है कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को स्वीकार किया जा सकता है और हम कर सकते हैं यू. पी. एस. सी. द्वारा अपनाई गई संक्षिप्त सूचीकरण की विधि में हस्तक्षेप नहीं किया है क्योंकि यह एक तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित प्रतीत होता है।

20. हालाँकि, इस मामले में हमने देखा है कि के अनुच्छेद 3.1 में यूपीएससी का विज्ञापन दिनांक 23.5.1998, लघु की विधि विज्ञापन के उक्त अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि आयोग उम्मीदवारों की संख्या को इन दोनों के आधार पर सीमित कर सकता है - विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता और अनुभव या विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक अनुभव के आधार पर या विज्ञापन में अनुभव के आधार पर प्रासंगिक क्षेत्र। दूसरे शब्दों में, यह यू. पी. एस. सी. के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए खुला था यह कहते हुए कि यह केवल उन लोगों को बुलाएगा जिनके पास कृषि में पीएचडी की डिग्री है (हालांकि आवश्यक डिग्री केवल कृषि में एम. एससी. की डिग्री थी)। इसी तरह, यूपीएससी कह सकता था कि वह केवल उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाएगा जिनके पास पांच साल का अनुभव है, हालांकि आवश्यक आवश्यकता केवल दो साल का अनुभव था।

हालांकि, एमएससी डिग्री प्राप्त करने के बाद के अनुभव को उच्चतर नहीं कहा जा सकता है। एम. एस. सी. की डिग्री प्राप्त करने से पहले का अनु भवइसके अलावा विज्ञापन दिनांक 23.5.1998 में यह उल्लेख नहीं है कि दो साल एम. एससी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद अनुभव होना चाहिए।

21. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमें कई तथ्य दिखाए हैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि अनुभव स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद होना चाहिए हालांकि, वर्तमान मामले में, विज्ञापन यह उल्लेख नहीं है कि दो साल का अनुभव कृषि एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद होना चाहिए। इसलिए हम इसमें शब्द नहीं जोड़ सकते। विज्ञापन को वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे वह है।

22. जैसा कि इस न्यायालय ने रमण दयराम शेट्टी बनाम में कहा है। द. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य, ए. आई. आर. (1979) एस. सी. 1628 (पैरा 10 द्वारा):

> "यह प्रशासनिक कानून का एक सुव्यवस्थित नियम है कि एक कार्यकारी प्राधिकारी को उन मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने कार्यों का न्याय किए जाने का दावा करता है और उसे सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए एक अधिनियम के उल्लंघन अमान्य होने के दर्द पर वे मानक उन्हें। इस नियम का प्रतिपादन श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने किया था विट्रेली बनाम सीटन में, (1959) 359 यू. एस. 535; 3 एल एड।

दूसरा 1012 जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

> "एक कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने कार्यों का दावा करती है न्याय किया। तदनुसार, यदि नौकरी से बर्खास्तगी है एक परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित, भले ही उदारता से परे आवश्यकताएँ जो ऐसी एजेंसी को बांधती हैं उस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से सावधानीपूर्वक निरीक्षण

किया जाए। यह न्यायिक रूप से विकसित नियम प्रशासनिक कानून अब दृढ़ता से स्थापित हो गया है और,यदि मैं जोड़ सकता हूं ठीक ही कहा है। जो प्रक्रियात्मक तलवार लेता है वह तलवार के साथ नष्ट हो जाएगा।"

इस न्यायालय ने इस नियम को भारत में वैध और लागू माना। ए.एस. अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य, [1975] 3 एससीआर 82: एआईआर (1975) एससी 984 और बाद के निर्णयों में, जो सुखदेव बनाम भगतराम, [1975] 3 एससीआर 619; एआईआर (1975) एससी 1331, मैथ्यू, जे. ने श्री जस्टिस की उपरोक्त टिप्पणियों को उद्धृत किया। स्वीकृति के साथ फ्रैंकफर्टर। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह नियम, हालांकि यह भी समर्थन योग्य है कि अनुच्छेद 14 से उत्पन्न होना केवल आधार नहीं है उस लेख पर। अनुच्छेद के अलावा इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। 14. यह प्रशासनिक कानून का एक नियम है जिसे न्यायिक रूप से लागू किया गया है। द्वारा मनमाना शक्ति के प्रयोग के खिलाफ एक चेक के रूप में विकसित किया गया कार्यकारी प्राधिकरण। अगर हम श्री न्यायमूर्ति के फैसले की ओर मुड़ते हैं संविधान लेकिन इसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कानून के परिणामस्वरू विकसित किया गया। इंग्लैंड में भी, प्रशासनिक कानून में हालिया प्रवृत्ति इसमें है पृष्ठ 540-541 में जो कहा गया उससे दिशा स्पष्ट है। प्रो. वेड का प्रशासनिक कानून चौथा संस्करण। इसका कोई कारण नहीं है हमें इस नियम को अपने निरंतर कार्य के प्रशासनिक कानून का विस्तार एक भाग के रूप में अपनाने में संकोच करना चाहिए।''

23. यूपीएससी के विज्ञापन में अनुच्छेद 3.1 नहीं था इसके चयन की संक्षिप्त सूची (बशर्ते कि यह निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण हो)। हालांकि, वर्तमान मामले में, एक विशेष तरीके से संक्षिप्त सूची बनाई गई है। पैरा 3.1 में विहित। इसलिए, यूपीएससी के लिए शॉर्ट-लिस्टिंग के किसी अन्य तरीके का सहारा लेना खुला नहीं है, भले ही ऐसी अन्य विधि को निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण कहा जा सके।

24. ऊपर दिए गए कारणों से, इस अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अपास्त कर दिया जाता है। अपीलार्थी उप निदेशक (कृषि) के पद पर 2001 से प्राधिकरण के निर्णय व इस न्यायालय के अंतरिम आदेश से कार्यरत है एवं हम उसकी नियुक्ति को बरकरार करते है। कोई लागत नहीं।

आर. पी. अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हनुमान सहाय मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।